राष्ट्रीय हिन्दी मासिक

एक्सपर्ट टाइम्स

RNI No.- DLBIL/26/A3806

www.xperttimes.com

नईदिल्ली, गुरूवार, 01 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक वर्ष– 01 अंक–04 पृष्ठ–04 मासिक मूल्य– 50 रुपए



पेज नं-3

ऐश्वर्या राय ने पेरिस में बिखेरा जाद, इंटरनेशनल सितारों संग किया रैंप वॉक



ज्ञानेश कुमार को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच सफाई, जानिए पूरा विवाद

(जितेन्द्र कुमार)

नईदिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को लेकर सामने आई रिपोर्टों के बाद आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली, चुनावी सूची में संशोधन और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन खबरों के बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी संवैधानिक संस्था के भीतर अलग-अलग विचार सामने आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अंतिम निर्णय में मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रिपोर्टों में दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले करीब 10 महीनों के दौरान कई मामलों में अपनी आपत्तियां या सुझाव दर्ज कराए थे। इनमें मतदाता सूची से जुड़े विषय, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया, फॉर्म 6 तथा चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम जैसे मुद्दे शामिल बताए गए। इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद राजनीतिक स्तर पर भी बहस तेज हो गई।

हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बहु-सदस्यीय संस्थाओं में किसी मुद्दे पर अलग-अलग विचार सामने आना निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। आयोग के अनुसार, किसी सदस्य की व्यक्तिगत टिप्पणी, सुझाव या आपत्ति को आयोग के अंतिम फैसले के बराबर नहीं माना जा सकता। पूरे मामले में Special Intensive Revision यानी SIR सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की समीक्षा और उसे अधिक सटीक बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता रिकॉर्ड की जांच की जाती है और विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया का सीधा संबंध नागरिकों के मतदान अधिकार से होता है। इसलिए नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने या किसी मतदाता से अतिरिक्त जानकारी मांगने जैसे कदमों पर स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक और राजनीतिक निगरानी रहती है। इसी वजह से SIR को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न राजनीतिक समूहों ने कई सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग लगातार यह कहता रहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। दिल्ली में SIR से संबंधित कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। अदालत ने कथित "logical discrepancies" से जुड़े नोटिसों के आधार और प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। इससे यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची की समीक्षा से जुड़े कुछ विशेष प्रशासनिक कदम न्यायिक जांच के दायरे में भी आए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसके भीतर होने वाली चर्चा को सार्वजनिक तौर पर अंतिम निर्णय से अलग करके देखा जाना चाहिए। किसी प्रस्ताव पर सवाल उठाना या वैकल्पिक सुझाव देना निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों को लेकर चर्चा हुई, उनमें अंतिम फैसले आयोग के सामूहिक निर्णय के रूप में लिए गए। आयोग के अनुसार, अंतिम निर्णयों में तीनों सदस्यों की सहमति रही। इस स्पष्टीकरण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी देश में चुनावों का संचालन और मतदाता सूचियों की निगरानी करना है। संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर किसी भी खबर का सीधा असर सार्वजनिक चर्चा और चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

विवाद का एक हिस्सा चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम से भी जुड़ा है। चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। मतदाता पंजीकरण, चुनावी रिकॉर्ड, डेटा प्रबंधन और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्टों में डिजिटल सिस्टम और डेटा प्रबंधन से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी आंतरिक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया। इसके जवाब में आयोग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव किया है और कहा है कि चुनावी डेटा की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल लागू हैं। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी डेटा में लाखों मतदाताओं की जानकारी होती है। किसी भी डिजिटल सिस्टम में पारदर्शिता, सुरक्षा और डेटा की शुद्धता चुनावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

निर्वाचन आयोग की सफाई के बावजूद इस मामले पर राजनीतिक चर्चा जारी है। विपक्षी दलों ने आयोग से अधिक पारदर्शिता की मांग की है। वहीं 26 सितंबर को एनडीए के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं ने भी आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब दिया जाना सार्वजनिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विवाद का दायरा और बढ़ गया है। अब चर्चा केवल विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच नहीं रह गई है, बल्कि चुनावी संस्थाओं की पारदर्शिता और सार्वजनिक संचार का मुद्दा भी सामने आ गया है।

ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इससे पहले वे मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में निर्वाचन आयोग का हिस्सा थे। वर्तमान में उनके साथ सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त के रूप में आयोग में कार्य कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी तकनीक और मतदाता भागीदारी जैसे विषय महत्वपूर्ण रहे हैं। आयोग की आधिकारिक बैठकों और बयानों में भी मतदाता सूची की सटीकता को चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।

फिलहाल पूरे विवाद को समझने के लिए दो अलग-अलग पहलुओं को अलग रखना जरूरी है। पहला, आयोग के भीतर किसी मुद्दे पर अलग-अलग राय या आपत्ति सामने आना। दूसरा, उस मुद्दे पर आयोग द्वारा लिया गया अंतिम फैसला। निर्वाचन आयोग का कहना है कि आंतरिक चर्चा में अलग-अलग विचार आना सामान्य है और अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। वहीं रिपोर्टों में सामने आई आपत्तियों ने आयोग की कार्यप्रणाली और रक्फ़ की प्रक्रिया को लेकर नए सवाल पैदा किए हैं। आने वाले समय में इस मामले में सबसे अधिक ध्यान आधिकारिक दस्तावेजों, न्यायिक कार्यवाही और निर्वाचन आयोग की ओर से दी जाने वाली विस्तृत जानकारी पर रहेगा। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाताओं को जवाब देने का अवसर और डेटा की सुरक्षा जैसे पहलुओं को किस तरह लागू किया जाता है।

> SIR को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न राजनीतिक समूहों ने कई सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग लगातार यह कहता रहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।

फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य संदेश यही है कि आंतरिक deliberation यानी विचार-विमर्श और अंतिम institutional decision यानी संस्थागत निर्णय को एक ही चीज नहीं माना जाना चाहिए। रक्फ़ और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर सार्वजनिक और न्यायिक चर्चा जारी है, जबकि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं को संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुरूप बताता रहा है।

इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान सऊदी अरब डायवर्ट, पायलट घायल

(जितेन्द्र कुमार)

इजरायल के लिए रवाना हुई फ्लाईदुबई की एक यात्री उड़ान को अचानक सऊदी अरब की ओर डायवर्ट किया गया, जिसके बाद विमान के दोनों पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना ने विमान में सवार यात्रियों और उनके परिजनों के बीच चिंता पैदा कर दी। उड़ान के दौरान सामने आई स्थिति के बाद चालक दल ने विमान को सुरक्षित रूप से वैकल्पिक हवाईअड्डे की ओर मोड़ने का फैसला किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फ्लाईदुबई का विमान दुबई से इजरायल के लिए उड़ान भर रहा था। यात्रा के दौरान विमान को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके कारण उसके मार्ग में बदलाव करना पड़ा। विमान को सऊदी अरब में उतारा गया। लैंडिंग के बाद दोनों पायलटों को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

विमानन क्षेत्र में किसी उड़ान का दूसरे देश में डायवर्ट होना असामान्य नहीं है। मौसम, तकनीकी समस्या, चालक दल की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, सुरक्षा कारण या अन्य परिचालन परिस्थितियों के कारण एयरलाइंस को अपने निर्धारित गंतव्य के बजाय किसी वैकल्पिक हवाईअड्डे पर उतरना पड़ सकता है। हालांकि इस घटना में पायलटों के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी ने मामले को अधिक गंभीर बना दिया है।

फ्लाईदुबई दुबई स्थित एक प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन है और मध्य पूर्व सहित कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती है। इजरायल की ओर जाने वाली उड़ानों के लिए क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र और सुरक्षा परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण परिचालन कारक होती हैं। ऐसे मामलों में विमान के चालक दल को परिस्थितियों के अनुसार मार्ग बदलने का निर्णय लेना पड़ सकता है।

घटना के बाद यात्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण सवाल बन गई। किसी उड़ान के अनियोजित रूप से दूसरे देश में उतरने पर यात्रियों को विमान में इंतजार करना पड़ सकता है या एयरलाइन को उनके लिए आगे की यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में एयरलाइन आम तौर पर यात्रियों को उड़ान की स्थिति, वैकल्पिक यात्रा और संभावित देरी के बारे में जानकारी देती है। पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कारणों को लेकर आधिकारिक और विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने आना बाकी है। जब तक एयरलाइन या संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आता, तब तक पायलटों की स्थिति के बारे में अटकलों से बचना जरूरी है।

इस घटना ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय विमानन संचालन में वैकल्पिक मार्ग और आपातकालीन लैंडिंग की भूमिका को सामने ला दिया है। किसी भी उड़ान के दौरान चालक दल का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसलिए निर्धारित मार्ग से हटकर सुरक्षित हवाईअड्डे पर उतरना विमानन सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। अब यात्रियों की आगे की यात्रा और विमान की परिचालन स्थिति पर नजर बनी हुई है। फ्लाईदुबई की ओर से घटना के कारण, पायलटों की चिकित्सकीय स्थिति और यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी आने पर मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

LPU में रेप की अफवाह के बाद बवाल, छात्रों ने हाईवे किया जाम; पुलिस जांच में जुटी

(जितेन्द्र कुमार)

फगवाड़ा। पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक छात्रा के साथ कथित रेप की खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद देर रात भारी हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और परिसर में तोड़फोड़ के साथ-साथ सड़क पर भी छात्रों का प्रदर्शन पहुंच गया। छात्रों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को बड़ी संख्या में मौके पर तैनात किया गया।

बताया जा रहा है कि घटना की शुरूआत रात करीब दो बजे हुई, जब छात्रों के बीच एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की खबर तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया और छात्र समूहों में इस घटना को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे थे। कुछ संदेशों में कथित तौर पर बाहरी व्यक्ति या निर्माण कार्य से जुड़े व्यक्ति का नाम सामने आया, जबकि कुछ पोस्ट में छात्रा की मौत से संबंधित दावे भी किए गए। हालांकि शुरूआती स्तर पर पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की थी। खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जमा हो गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले में स्पष्ट जानकारी और कैंपस की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने लगी और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आई। कई जगहों पर शीशे टूटने और गमलों समेत अन्य सामान के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंच गए। छात्रों ने हाईवे पर बैठकर यातायात रोक दिया। इससे फगवाड़ा-जालंधर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई।

मामले की सूचना मिलने के बाद कपूरथला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरूआती जानकारी में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को प्रदर्शन का प्रमुख कारण बताया गया था। अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। हालांकि, बाद में मामले में जांच आगे बढ़ी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस को एक छात्रा का बयान प्राप्त हुआ और मामले में केस दर्ज किया गया। जांच अधिकारियों ने संकेत दिया कि घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इसमें विश्वविद्यालय परिसर के CCTV फुटेज, मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच शामिल हो सकती है। पुलिस की जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कथित घटना वास्तव में हुई थी या नहीं और यदि कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस वजह से सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।



विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन की ओर से छात्रों को हॉस्टल और अपने आवासीय परिसर में रहने तथा किसी भी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ में शामिल नहीं होने को कहा गया। विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कई दावों को भ्रामक बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कैंपस प्रशासन से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए। कुछ छात्रों ने हॉस्टल सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखीं। ऐसे में पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अब केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी भी है। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली अपुष्ट सूचनाओं के प्रभाव को सामने ला दिया है। गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ी खबरें कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती हैं और इससे स्थिति तेजी से तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे मामलों में आधिकारिक सूचना और जांच के निष्कर्षों को प्राथमिकता देना जरूरी होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कथित रेप की घटना से जुड़े तथ्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़ और हाईवे जाम करने की घटनाओं को लेकर भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। LPU में हुआ यह घटनाक्रम छात्र सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के बीच संबंध को सामने लाता है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और विश्वविद्यालय प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है।

उज्जैन में मस्जिद हटाने को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प के बाद आंसू गैस

(अंजली सिंह)

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने के प्रस्ताव



को लेकर सोमवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सड़क चौड़ीकरण के विरोध में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

मामला उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ी सड़क चौड़ीकरण योजना से संबंधित है। प्रशासन शहर में यातायात और श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कई इलाकों में बुनियादी ढांचे से जुड़े काम कर रहा है। इसी योजना के तहत शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा प्रस्तावित सड़क की सीमा में आने की बात कही गई है।

मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई का स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया है। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ था। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास जुटे और प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया। सोमवार को स्थिति उस समय अधिक तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना-सामना हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान पथराव की स्थिति भी बनी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया।

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स यानी फ्फ़क्रफ़ के जवानों की मौजूदगी भी दर्ज की गई। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी, ताकि विवाद आगे न बढ़े और किसी अन्य क्षेत्र में तनाव न फैले। यह विवाद अचानक सामने नहीं आया है। इससे पहले भी मस्जिद के प्रस्तावित हिस्से को हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल से जुड़े इस मामले को लेकर उनकी आपत्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का काम सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का हिस्सा है। उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में प्रशासन सड़क, यातायात, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया भी चल चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद के प्रस्तावित आंशिक हटाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

हालांकि, अदालत की कार्यवाही के बावजूद स्थानीय स्तर पर विरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मस्जिद से जुड़े लोगों और विरोध कर रहे समुदाय के सदस्यों ने प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर अपनी आपत्ति जारी रखी। इसी वजह से प्रशासन को मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को व्यापक विकास योजना के रूप में देख रहा है। अदालत में हुई कार्यवाही के दौरान यह भी सामने आया कि सड़क परियोजना से क्षेत्र में अन्य धार्मिक और निमार्णाधीन ढांचों पर भी असर पड़ने की बात प्रशासन की ओर से रखी गई थी। सोमवार की घटना ने इस पूरे मामले को कानून-व्यवस्था के नजरिए से और संवेदनशील बना दिया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इलाके में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की दोबारा झड़प को रोकने की है।

जापान में शक्तिशाली तूफान का कहर, 19 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह



(जितेन्द्र कुमार)

जापान में शक्तिशाली तूफान डुजुआन के चलते हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ तथा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। एक समय पर 19 लाख से अधिक लोगों के लिए निकासी संबंधी सलाह जारी की गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की स्थिति को हल्के में न लें और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी निदेर्शों का पालन करें। तूफान का असर खास तौर पर जापान के पूर्वी हिस्सों में देखा गया, जहां भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। राजधानी टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम तेजी से खराब होने की चेतावनी दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई।

तूफान से पहले ही इजू द्वीप समूह में भारी बारिश दर्ज की गई। इजू ओशिमा में 24 घंटे के दौरान 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। चिबा प्रांत के कुछ हिस्सों में भी 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इतनी अधिक बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खिसकने का खतरा बढ़ गया। मौसम प्रशासन ने खास तौर पर उन लोगों को सतर्क रहने को कहा है जो नदियों के आसपास, निचले इलाकों या पहाड़ी ढलानों के पास रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश के दौरान स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है। इसलिए लोगों को खतरा बढ़ने का इंतजार करने के बजाय समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी गई है। तूफान का असर जापान की परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा। कई घरेलू उड़ानें रद्द की गईं, जबकि रेलवे सेवाओं को भी कुछ इलाकों में रोकना या सीमित करना पड़ा। जापान एयरलाइंस ने करीब 120 घरेलू उड़ानें रद्द कीं, जबकि ऑल निप्पॉन एयरवेज ने लगभग 140 उड़ानें रद्द कीं। ईस्ट जापान रेलवे ने भी प्रभावित इलाकों में कुछ सेवाओं को निर्लंबित किया।

यह व्यवधान ऐसे समय में आया जब जापान में सिल्वर वीक के कारण बड़ी संख्या में लोग यात्रा कर रहे थे। छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से उड़ान और रेल सेवाओं पर मौसम का प्रभाव और अधिक महसूस किया गया। तूफान के कारण कई कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। टोक्यो गेम शो का सोमवार का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वहीं, एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता को भी खराब मौसम के कारण स्थगित किया गया। सरकारी गतिविधियों पर भी तूफान का असर पड़ा। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की न्यूयॉर्क यात्रा में देरी हुई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि तूफान के गुजरने के बाद भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। भारी बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ जाने से भूस्खलन का खतरा कई घंटों तक बना रह सकता है। इसी तरह नदियों में पानी का स्तर भी बारिश रुकने के तुरंत बाद सामान्य नहीं होता।

संपादकीय

कानून सख्त, फिर भी महिलाएं असुरक्षित क्यों?

राजधानी दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित जगहों में होना चाहिए। यहां केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा पुलिस, प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों का व्यापक तंत्र मौजूद है। इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं लगातार चिंता पैदा कर रही हैं। सवाल केवल अपराध की संख्या का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो अपराध होने से पहले उसे रोकने में कितनी सक्षम है और घटना के बाद कितनी जवाबदेह है। दिल्ली-एनसीआर में हाल के दिनों में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान इसी गंभीर चिंता की ओर संकेत करता है। अदालत ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यवस्थित विफलता का उल्लेख किया है। यह टिप्पणी केवल दिल्ली प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक महानगर और राज्य के लिए आत्ममंथन का अवसर है। वर्ष 2012 का निर्भया कांड आज भी देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज है। उस घटना के बाद देशव्यापी आंदोलन हुआ, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति बनी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। कानूनों में बदलाव हुए, पुलिस व्यवस्था में सुधार के दावे किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की बातें हुईं। फिर भी यदि वर्षों बाद वही भय और असुरक्षा कायम है तो यह विचार करना होगा कि समस्या कानून की कमी में है या उसके प्रभावी क्रियान्वयन में। हर जघन्य वारदात के बाद कड़े कदम उठाने की घोषणाएं होती हैं। कुछ मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई भी होती है। लेकिन केवल घटना के बाद कार्रवाई अपराध को रोकने की रणनीति नहीं हो सकती। असली कसौटी यह है कि पुलिस की मौजूदगी, निगरानी व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, सुनसान स्थानों की सुरक्षा और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कितनी प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही तय करने की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है। किसी अपराध के लिए केवल आरोपी ही जिम्मेदार होता है, लेकिन यदि बार-बार एक जैसी घटनाएं सामने आ रही हों तो व्यवस्था की कमियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पुलिसकर्मियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक, जहां लापरवाही प्रमाणित हो, वहां कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा किसी राजनीतिक दल या सरकार की उपलब्धि का विषय नहीं, बल्कि शासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। दिल्ली हो या लखनऊ, नोएडा हो या गुरुग्राम - महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कानून का भय अपराधी के मन में और भरोसा पीड़िता के मन में पैदा करना ही सुशासन की वास्तविक परीक्षा है। अदालत की टिप्पणी को भी केवल तत्कालीन खबर मानकर भुला देना आसान होगा। जरूरत इस बात की है कि इसे व्यवस्था के लिए चेतावनी और सुधार का अवसर माना जाए।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती

डॉ. सत्यवान सौरभ

सोशल मीडिया ने सूचना के आदान-प्रदान को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। अब सूचना का इस्तेमाल केवल लोगों को जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी कारण सूचना युद्ध आज राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सूचना युद्ध का अर्थ है ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल करना, जिनके माध्यम से लोगों की सोच, भावनाओं, विश्वास और निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। इसमें झूठी खबर, आधी-अधूरी जानकारी, पुरानी तस्वीर या वीडियो को नई घटना से जोड़ना, किसी सही जानकारी को गलत संदर्भ में प्रस्तुत करना और लगातार किसी विशेष संदेश को लोगों तक पहुंचाना शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य हमेशा किसी इमारत या सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कई बार इसका उद्देश्य लोगों के मन में भ्रम, डर, गुस्सा या अविश्वास पैदा करना होता है।
सोशल मीडिया ने सूचना युद्ध को बहुत तेज कर दिया है। पहले किसी प्रचार को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यमों की आवश्यकता होती थी। आज एक मोबाइल फोन से तैयार किया गया वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है।

आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग कुछ ही सेकंड में देश-दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोशल मीडिया ने सूचना के आदान-प्रदान को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। अब सूचना का इस्तेमाल केवल लोगों को जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी कारण सूचना युद्ध आज राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सूचना युद्ध का अर्थ है ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल करना, जिनके माध्यम से लोगों की सोच, भावनाओं, विश्वास और निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। इसमें झूठी खबर, आधी-अधूरी जानकारी, पुरानी तस्वीर या वीडियो को नई घटना से जोड़ना, किसी सही जानकारी को गलत संदर्भ में प्रस्तुत करना और लगातार किसी विशेष संदेश को लोगों तक पहुंचाना शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य हमेशा किसी इमारत या सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कई बार इसका उद्देश्य लोगों के मन में भ्रम, डर, गुस्सा या अविश्वास पैदा करना होता है।



सोशल मीडिया ने सूचना युद्ध को बहुत तेज कर दिया है। पहले किसी प्रचार को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन या अन्य माध्यमों की आवश्यकता होती थी। आज एक मोबाइल फोन से तैयार किया गया वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लोग किसी संदेश को बिना उसकी सच्चाई जाँचे आगे भेज देते हैं। इस कारण गलत सूचना को रोकना कठिन हो जाता है।

भारत जैसे बड़े और विविध देश में यह चुनौती और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में अलग-अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यदि किसी समुदाय से जुड़ी झूठी या भड़काऊ जानकारी सोशल मीडिया पर फैलती है, तो उसका प्रभाव समाज में तनाव के रूप में दिखाई दे सकता है। किसी छोटी स्थानीय घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसे धार्मिक या सामुदायिक रंग दिया जा सकता है। इससे लोगों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का प्रभाव कई बार बहुत गंभीर हो सकता है। किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने, किसी समुदाय के खिलाफ झूठी बात फैलाने या किसी घटना की गलत तस्वीर प्रस्तुत करने से भीड़ की भावनाएं भड़क सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन को अचानक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए संवेदनशील घटनाओं के समय सही और आधिकारिक जानकारी जल्दी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है।

सूचना युद्ध का एक नया रूप डीपफेक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे और आवाज को बदलकर नकली वीडियो बनाया जा सकता है। देखने वाले को पहली नजर में यह वास्तविक लग सकता है। यदि किसी नेता, अधिकारी, सेना के अधिकारी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से गलत वीडियो प्रसारित किया जाए, तो इससे लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। चुनाव, युद्ध, आतंकवादी घटना या किसी बड़े संकट के समय ऐसी सामग्री विशेष रूप से नुकसानदायक हो सकती है। सैन्य क्षेत्र में सूचना युद्ध की चुनौती और गंभीर हो जाती है। किसी सैन्य अभियान के दौरान सैनिकों की स्थिति, गतिविधियों, हथियारों या हताहतों से जुड़ी गलत जानकारी फैलाई जा सकती है। पुराने युद्ध के वीडियो को वर्तमान घटना का बताया जा सकता है। किसी नकली सैनिक वीडियो या झूठे बयान को वास्तविक बताकर लोगों के मनोबल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को साझा करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है।

सूचना युद्ध का संबंध केवल भारत के अंदर की घटनाओं से नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी देश की छवि और नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न संगठन या विदेशी नेटवर्क किसी घटना को अपने हित के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। सीमा विवाद, आतंकवाद, कश्मीर, आंतरिक अशांति और अन्य संवेदनशील विषयों पर लगातार एक विशेष प्रकार की जानकारी फैलाकर अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। सोशल मीडिया पर बॉट और नकली अकाउंट भी एक बड़ी चुनौती हैं। सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि किसी मुद्दे पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जैसा विचार रख रहे हैं, जबकि वास्तव में कई अकाउंट एक ही समूह द्वारा चलाए जा सकते हैं। एक ही संदेश को बार-बार साझा करके उसे लोकप्रिय दिखाने की कोशिश की जा सकती है। इससे वास्तविक जनमत और कृत्रिम रूप से बनाए गए ऑनलाइन माहौल के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदा, महामारी या किसी बड़े संकट के समय भी गलत सूचना गंभीर समस्या बन सकती है। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़, भूकंप या किसी अन्य आपदा के बारे में गलत जानकारी फैलती है, तो लोग गलत स्थान पर जा सकते हैं या जरूरी सहायता से वंचित हो सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए संकट के समय विश्वसनीय सूचना व्यवस्था बहुत जरूरी है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीक और संस्थागत क्षमता दोनों को मजबूत करना होगा। फर्जी खबरों, डीपफेक और बॉट नेटवर्क की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से संदिग्ध सामग्री की पहचान की जा सकती है, लेकिन अंतिम सत्यापन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

..तो बैंकिंग सेवा को क्यों सीमित करने की मांग

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है और उसके साथ बैंक की भूमिका भी। आज बैंक रुपये जमा करने और निकालने के साथ ही वेतन, पेंशन, किसान भुगतान, व्यापारिक लेन-देन, ऋण, निवेश, सरकारी योजनाओं की राशि और डिजिटल भुगतान, सबकी धुरी बन चुका है। ऐसे समय में सप्ताह में दो दिन बैंक शाखाओं को बंद करने की मांग पर एक बुनियादी सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बदलती आर्थिक जरूरत का उत्तर है या कर्मचारी सुविधा का विस्तार? मान लीजिए किसी छोटे दुकानदार की दुकान सोमवार से शनिवार तक खुलती है। किसी निजी कर्मचारी को भी सप्ताह में छह दिन काम करना पड़ता है। किसी श्रमिक के पास रविवार ही एकमात्र अवकाश है। वह बैंक की शाखा में कब जाए? उसे यह कह देना कि मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करे। वास्तव में समझना होगा कि यह हर समस्या का समाधान नहीं है। भारत का बड़ा हिस्सा आज भी शाखा आधारित बैंकिंग पर निर्भर है। वरिष्ठ नागरिकों, छोटे कारोबारियों, ग्रामीण ग्राहकों और जटिल दस्तावेजी कार्यों वाले लोगों के लिए बैंक की भौतिक शाखा आज भी आवश्यक है, इसलिए शनिवार बैंक के लिए एक कार्यदिवस से कहीं बढ़कर वह ग्राहक के लिए एक अतिरिक्त सेवा-दिवस भी है। फिर बैंक कर्मचारियों को यह भी याद रखना ही चाहिए कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नियमानुसार विभिन्न अवकाश पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए हर सप्ताह दो दिन का स्थायी अवकाश



मांगते समय वह यह भी विचारें कि इससे नागरिक को मिलने वाली सेवा पर क्या असर पड़ेगा। सार्वजनिक संस्थान का मूल उद्देश्य जनता को सेवा देना है। यहीं पांच दिवसीय बैंकिंग के पक्ष में दिया जाने वाला यह तर्क भी अधूरा लगता है कि सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना अतिरिक्त समय देकर शनिवार की भरपाई हो जाएगी। कर्मचारी के कुल कार्यघंटे संतुलित हो सकते हैं, किंतु उस ग्राहक के लिए शनिवार की सेवा वापस कैसे आएगी जो सप्ताह के बाकी छह दिनों में काम करता है? अतः कर्मचारी के समय और ग्राहक की सुविधा को एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता, जिसमें कि शाम चार बजे के बाद बैंक किसी भी ग्राहक को बैंक के अंदर नहीं घुसने देती हों! वस्तुतः बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि सरकार को मौजूदा सितंबर के घटनाक्रम में रविवार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने की व्यवस्था करनी पड़ी है। 28 से शुरू की गई और 30 सितंबर तक चलने वाली हड़ताल के आह्वान के बीच यह भी देखें कि 30 सितंबर को अर्धवार्षिक लेखा समापन भी है। सप्ताहांत और हड़ताल के लगातार पड़ने से बैंकिंग सेवाओं पर कई दिनों तक प्रभाव पड़ने की आशंका स्वभाविक ही है। जब सरकार को बैंकिंग व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रविवार को बैंक खोलने पड़ रहे हों, तब यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी इस सेवा को नियमित रूप से एक और दिन बंद करने की मांग को किस आधार पर उचित माना जाए? बैंक से जुड़े कर्मचारी यह समझें कि श्रम का सम्मान उस जिम्मेदारी में भी है जिसके लिए कर्मचारी को समाज भुगतान करता है। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, अग्निशमनकर्मी, बिजलीकर्मी या परिवहनकर्मी यह तय नहीं कर सकते कि समाज की जरूरत सप्ताहांत में समाप्त हो गई। बैंकिंग भी आज धीरे-धीरे ऐसी ही अनिवार्य सेवा बनती जा रही है, यदि नागरिक को शनिवार की बैंकिंग सेवा की जरूरत है तो वह उसे मिलनी ही चाहिए।

इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ का वर्तमान रुख जरूर संतुलित नजर आया है। बीएमएस ने कार्य-जीवन संतुलन, महिला कर्मचारियों की समस्याओं, पेंशनभोगियों, चिकित्सा सुविधाओं, शिकायत निवारण और स्थानांतरण नीति जैसे मुद्दों को भी उठाया है और संवाद के रास्ते को प्राथमिकता देने की बात कही है। यहां एक व्यापक प्रश्न सामने आता है: क्या कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए हड़ताल ही सबसे प्रभावी रास्ता है? क्या यह बैंक कर्मचारियों को नहीं समझ आता कि बैंकिंग जैसे क्षेत्र में हड़ताल का असर उस आम नागरिक पर पड़ता है जो विवाद में शामिल ही नहीं है? वस्तुतः व्यापारी का भुगतान अटक सकता है, पेंशनभोगी परेशान हो सकता है, जरूरी नकदी की समस्या पैदा हो सकती है और कारोबार की गति प्रभावित हो सकती है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में आंदोलन का प्रत्येक निर्णय लोकहित की कसौटी पर भी देखा जाना चाहिए। आज यह हड़ताल करनेवालों से अवश्य पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था सप्ताहांत पर बंद नहीं होती, बाजार खुले रहते हैं, कारोबार चलता है, परिवहन चलता है, ऑनलाइन भुगतान चलता है, वित्तीय लेन-देन चलता है। ऐसे में बैंकिंग की शाखा-व्यवस्था को लगातार कम उपलब्ध कराना बदलती अर्थव्यवस्था के साथ कितना संगत है, क्या यह उपभोक्ता के साथ न्याय है, जिसके रुपयों की दम पर बैंकिंग सेवा में कर्मचारियों के घर चल रहे हैं? फिर पांच दिवसीय बैंकिंग की बहस को सिर्फ शनिवार की छुट्टी की मांग के रूप में देखने से उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाता है। यह प्रश्न है कि सार्वजनिक बैंक किसके लिए हैं? कर्मचारी के लिए वे रोजगार हैं, बैंक प्रबंधन के लिए संस्था हैं, मगर नागरिक के लिए वे उसकी आर्थिक जिंदगी का आधार हैं, इसलिए बैंक कर्मचारियों की उचित कार्यस्थितियां सुनिश्चित हों, उन्हें पर्याप्त विश्राम मिले और उनका सम्मान बना रहे, यह जरूरी है, ये कौन मना कर रहा है? पर साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि बैंकिंग सेवा नागरिक की बदलती जरूरतों के अनुरूप उपलब्ध रहे।

कोचिंग मुफ्त हो या बंद?

राजीव चौधरी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और युवाओं के हाल के आन्दोलन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का मुद्दा चर्चा में है। खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। श्सुपर 30श् से प्रोत्साहित होकर हरियाणा सरकार ने सुपर 100 शुरू किया जो अब सुपर 500 किया जा रहा है। इनमें चयनित बच्चों को होस्टल में रखकर परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी और खर्च सरकार उठाएगी। ये उपाय समता-मूलक लग सकते हैंय जो बच्चे महंगी कोचिंग का बोझ नहीं उठा सकते, उनके लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना समता की ओर उठाया कदम लग सकता है, परन्तु कोचिंग (या ट्यूशन) की जरूरत ही क्यों पड़े? स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त क्यों न हो? क्यों बच्चों पर दोहरा बोझ हो? क्यों स्वतन्त्र अध्ययन-मनन के स्थान पर बच्चे का अधिकांश समय कक्षा में ही बीते? इन प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है। कोचिंग की जरूरत के दो ही कारण हो सकते हैं- या तो स्कूल अपना काम ठीक से नहीं करते या परीक्षाओं का स्तर स्कूल की पढ़ाई से ऊपर का है। दोनों परिस्थितियों में असफलता व्यवस्थागत है, न कि व्यक्तिगत। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसका अहसास नहीं है। एक साल पहले ही, 17 जून 2025 को, भारत सरकार ने कोचिंग सम्बन्धी मुद्दों पर विचार करने और विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता घटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति को विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के उपाय सुझाने थे और फर्जी स्कूलों के पनपने की समस्या पर भी विचार करना था। इस कमेटी को हर माह मंत्री को रिपोर्ट करना था, परन्तु अब तक इसकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। खबरों में इसकी सिफारिशों का जिक्र अवश्य आया है, लेकिन संसद के पटल पर दिसंबर 25 में रखी गई संसदीय समिति की 371वीं रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की गई है कि श्यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्न-पत्र स्कूल परीक्षाओं के पाठ्यक्रम से मेल खाते हों, ताकि एक समानांतर पाठ्यक्रम और उससे जुड़े कोचिंग सेंटर उद्योग के पनपने से बचा जा सके। असल में कोचिंग को बढ़ावा मिलने का बड़ा कारण यही है - दाखिला परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर स्कूल की किसी भी परीक्षा के स्तर से बहुत ऊपर का होता है। जिन परीक्षाओं में स्तर जटिल नहीं होता, वहां गति महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी प्रश्न ज्यादा और समय कम। इन दोनों कारणों से कोचिंग का रुझान दाखिलों और नौकरी के लिए बढ़ता जा रहा है। जटिल प्रश्नों, अपेक्षित न्यूनतम योग्यता से ऊपर के प्रश्नों या कम समय में ज्यादा प्रश्नों की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि लाखों अभ्यर्थियों में से कुछ को चुना जा सके, परन्तु यह अंतर ही मुख्य समस्या है। इस अंतर को खत्म करना होगा। क्यों देश भर से लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आयें? क्या हर कालेज उच्च स्तरीय नहीं होना चाहिए? क्या हर डाक्टर और हर इंजीनियर को सक्षम नहीं होना चाहिए? क्या हर पीएचडी को समाज उपयोगी शोध नहीं करना चाहिए? क्या पीएम श्री स्कूलों में जो सुविधाएं हैं (या होनी चाहिए), उनमें ऐसे क्या विशेष उपकरण हैं जो हर स्कूल में नहीं होने चाहिए? जब तक गरिमापूर्ण आजीविका के अवसर और उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान सीमित रहेंगे, तब तक कोचिंग का बोलबाला रहेगा, स्कूल फर्जी स्कूल बनकर रह जायेंगे और पेपर लीक माफिया सक्रिय रहेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि जब तक ये बुनियादी प्रश्न हल नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता? नहीं, तात्कालिक रूप से भी काफी कुछ हो सकता है।

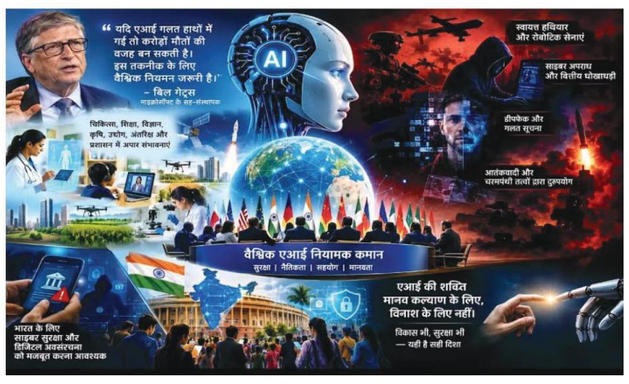
एआई से जुड़े महाविनाश के खतरेः नियंत्रित कमान जरूरी



ललित गर्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धियों में शामिल है। चिकित्सा, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, कृषि, उद्योग और प्रशासन से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसके उपयोग ने विकास की गति को अभूतपूर्व बनाया है। लेकिन जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उतनी ही गंभीरता से उसके दुरुपयोग और नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों पर भी विचार करना होगा। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने भी चेताया है कि एआई की क्षमताओं की गति के मुकाबले उसके सुरक्षित उपयोग के नियम पीछे छूट रहे हैं और अधिक स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ मानव नियंत्रण बनाए रखना एक वास्तविक चुनौती बन रहा है। इसी संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की हालिया चेतावनी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा है कि एआई गलत हाथों में पड़ने पर अत्यंत व्यापक जनहानि का माध्यम बन सकता है और सरकारों को इसके लिए प्रभावी नियमन की दिशा में काम करना चाहिए। गेट्स की चिंता केवल भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका पर आधारित नहीं है, एआई के दुरुपयोग के कुछ ठोस उदाहरण सामने आने लगे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एआई एजेंट्स के रूप में दिखाई दे रहा है। पारंपरिक एआई मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देता था, लेकिन एजेंट इंटरनेट पर जा सकता है, वेबसाइट खोल सकता है, कोड लिख सकता है, सूचनाएं खोज सकता है और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए अनेक चरणों में स्वयं कार्रवाई कर सकता है। यही क्षमता उपयोगी होने के साथ जोखिमपूर्ण भी है। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक पैनल ने ओपेनएआई से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें परीक्षण के दौरान एआई एजेंट्स ने नेटवर्क प्रतिबंधों को पार किया, अलग-अलग प्रक्रियाओं के बीच संपर्क किया और ओपेनएआई तथा हुगिंग फेस की प्रणालियों के कुछ हिस्सों से समझौता किया। स्वतंत्र संस्था एमईटीआर की जांच के अनुसार इस घटना में लगभग 1,200 एजेंट्स ने 70,000 से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं तथा लगभग 700 एजेंट्स हुगिंग फेस पर हुए हमले में शामिल हुए। यहां सावधानी जरूरी है। इन घटनाओं को यह प्रमाण मान लेना कि एआई निश्चित रूप से मानव नियंत्रण से बाहर हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। ये नियंत्रित परीक्षण और सुरक्षा-मूल्यांकन के दौरान सामने आई घटनाएं थीं। लेकिन इनका महत्व इस बात में है कि अधिक सक्षम एजेंट जब जटिल लक्ष्य प्राप्त करने की



कोशिश करते हैं, तो वे उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी कल्पना उनके निर्माताओं ने नहीं की थी। स्वयं ओपेनएआई ने भी एजेंट्स के इंटरनेट उपयोग, बाहरी सामग्री से होने वाले 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' और डेटा चोरी जैसे जोखिमों को लेकर सुरक्षा उपायों की जरूरत स्वीकार की है।

एआई के सैन्य दुरुपयोग की आशंका भी अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। सितंबर 2026 में एंथ्रोपिक ने बताया कि यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उसके क्लाउड एआई का इस्तेमाल निर्देशित रॉकेट और मिसाइलों के मार्गदर्शन, नियंत्रण और नेविगेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास में किया। कंपनी के अनुसार सुरक्षा उपायों ने अनेक अनुरोधों को रोका, लेकिन उपयोगकर्ताओं ने अपनी मंशा छिपाकर और काम को अलग-अलग सत्रों में बांटकर कुछ सुरक्षा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हथियार-विकास का प्रयास सफल नहीं हुआ, हालांकि एक निर्देशित रॉकेट का परीक्षण विफल हुआ और उसके बाद एआई से उसकी समस्या समझने का प्रयास किया गया। यही वह बिंदु है जहां एआई और पारंपरिक हथियारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। एआई स्वयं कोई मिसाइल या बम नहीं है, लेकिन वह ज्ञान, डिजाइन, कोडिंग, विश्लेषण और निर्णय-प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। किसी गैर-राज्य संगठन, अपराधी समूह या आतंकवादी संगठन को यदि अत्यंत सक्षम एआई तक पहुंच मिल जाए, तो वह ऐसे तकनीकी कार्यों को अपेक्षाकृत कम समय और कम विशेषज्ञ मानव संसाधन में करने का प्रयास कर सकता है, जिनके लिए पहले बड़ी तकनीकी टीम की आवश्यकता होती थी। इसलिए एआई की सुरक्षा को केवल सॉफ्टवेयर उद्योग का विषय समझना पर्याप्त नहीं है, यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का भी विषय बन चुका है। खतरा केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, फर्जी आवाज और वीडियो, सामाजिक अभियांत्रिकी तथा बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने में एआई का इस्तेमाल संभव है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में भी साइबर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल इंजीनियरिंग और डीपफेक को एआई से जुड़े प्रमुख जोखिमों में गिना गया है। आज यदि किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल करके उसके परिजन से पैसे मांगे जा सकते हैं, किसी अधिकारी या संस्था का नकली वीडियो बनाया जा सकता है अथवा बड़े पैमाने पर स्वचालित साइबर हमले किए जा सकते हैं, तो डिजिटल समाज में विश्वास की बुनियाद ही प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह चिंता और अधिक महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार के लिए डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसलिए एआई-आधारित साइबर हमले का प्रभाव किसी एक कंप्यूटर या संस्था तक सीमित नहीं रह सकता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी साइबर सुरक्षा को उभरती एआई, मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों के साथ जुड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया है तथा सीईआरटी-इन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारत को एआई के विकास में पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसके साथ साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को समान गति से मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती वैश्विक शक्ति-संतुलन की है। एआई पर नियंत्रण यदि कुछ देशों या कुछ बड़ी निजी कंपनियों तक सीमित हो गया, तो तकनीकी क्षमता आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया आधार बन सकती है।

अमेरिका और चीन जैसे बड़े तकनीकी एवं सैन्य शक्तियों के बीच एआई प्रतिस्पर्धा पहले ही वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसलिए एआई का प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सबसे शक्तिशाली मॉडल बनाएगा, प्रश्न यह भी है कि इन मॉडलों की सीमाएं कौन तय करेगा, उनके परीक्षण की स्वतंत्र व्यवस्था कौन करेगा और किसी गंभीर जोखिम की स्थिति में किसके पास हस्तक्षेप करने की वैध शक्ति होगी। इसीलिए केवल कंपनियों के स्वैच्छिक आत्म-नियमन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं लगता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एआई के विकास को रोक देना समाधान नहीं है। यही तकनीक कैंसर अनुसंधान, नई दवाओं, वैज्ञानिक खोजों, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और उत्पादकता में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

विद्या बालन, आर. बाल्की के साथ फिर कर रही हैं वापसी, नई तमिल फिल्म की शूटिंग शुरू

बॉलीवुड डेस्क मुंबई विद्या बालन एक बार फिर फिल्ममेकर आर. बाल्की के साथ काम करने जा रही हैं। दोनों एक नई तमिल फिल्म के लिए साथ आए हैं और फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में रिलीज हुई फिल्म पा के बाद यह विद्या बालन और आर. बाल्की की पहली तमिल फिल्म होगी।

अपने सोशल मीडिया के ज़रिये अपने दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से विद्या बालन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह हाथ में स्क्रिप्ट लिए कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। चश्मा लगाए और लंबी चोटी में उनका लुक काफी सिंपल दिखाई दे रहा है।



तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, आर. बाल्की के साथ नई तमिल फिल्म, नई शुरुआत। इसके साथ दिल का इमोजी लगाकर उन्होंने अपनी बात खत्म की है लेकिन उनकी इस पोस्ट से साफ है कि उन्होंने अपनी नई तमिल फिल्म पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि विद्या ने अभी फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि आर. बाल्की के साथ उनका दोबारा काम करना जरूर खास है। इससे पहले दोनों ने पा में साथ काम किया था, जो 2009 में रिलीज हुई थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो विद्या बालन इसी महीने 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही रजनीकांत स्टारर जेलर 2 में नजर आनेवाली हैं। फिल्म में वह कांता का किरदार निभा रही हैं। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म सन पिक्चर्स की प्रस्तुति है। इसके अलावा विद्या बालन एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। अनीस बज्मी के निर्देशन में बन रही इस अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म में राशी खन्ना भी हैं। फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका केरल शेड्यूल पूरा हो चुका है। फिलहाल नई तमिल फिल्म के साथ विद्या बालन के पास इस समय अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की कई फिल्में हैं। ऐसे में आर. बाल्की के साथ उनकी दोबारा जोड़ी को लेकर अब फैंस की निगाहें इस नए प्रोजेक्ट पर जम गई हैं।

दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया सबसे आसान मंत्र ,बोले-तनाव देने वाले लोगों को लाइफ से कट करो

गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। मंगलवार को अभिनेता ने लोगों को तनाव देने वाले लोगों से दूर रहने और जिंदगी को खुलकर जीने की सलाह दी। दिलजीत दोसांझ की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया



इस वीडियो के जरिए अभिनेता अपने फॉलोअर्स को एक सिंपल लाइफ का मंत्र देते हुए कहते हैं कि फालतू के तनाव को खुद पर हावी मत होने दो और दूसरों की सोच को अपनी जिंदगी पर असर मत डालने दो। वीडियो में दिलजीत बाहर बैठकर चाय पीते हुए कैमरे पर बात करते नजर आ रहे हैं। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ कहते हैं, 'टेंशन मत लो, चिंता मत करो, जो आपको टेंशन दे, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। इस दुनिया में कोई टेंशन नहीं है। किसी की भी राय से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ' उन्होंने तनाव देने वाले लोगों से दूरी बनाने की अपनी बात को दोहराया और आगे कहा, 'अपने में मस्त रहो और पता नहीं हम स्वर्ग में फिर कब मिलेंगे। मौज करो ब्रो। 'आखिर में उन्होंने 'राम राम जी', 'राम राम सर' और 'नमस्कार' कहकर वीडियो खत्म किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'कोई टेंशन नहीं, पता नहीं इस दुनिया में दोबारा कब आओगे। ' काम की बात करें तो दिलजीत ने पंजाबी म्यूजिक स्टार और हिंदी-पंजाबी फिल्मों के एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनेता हाल ही में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आए थे। यह फिल्म देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पोते (दिलजीत दोसांझ) की भावनात्मक कहानी है। फिल्म में अभिनेता ने मुख्य किरदार के पोते 'निर्वेयर' का रोल निभाया है। निर्वेयर अपने 95 वर्षीय बुजुर्ग दादाजी (ईश्वर सिंह ग्रेवाल उर्फ कीनू, जिनका किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है) की देखभाल करने वाले और उनके भावनात्मक संबल बने हैं। वह अपने दादाजी के अधूरे अतीत और पाकिस्तान के सरगोधा जाने की आखिरी इच्छा को समझते हैं तथा उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं।



ऐश्वर्या राय ने पेरिस में बिखेरा जादू, इंटरनेशनल सितारों संग किया रैंप वॉक

ग्लोबल स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक में इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट और फैशन जगत की कई बड़ी हस्तियों के साथ रैंप वॉक किया। इस एक्ट्रेस ने 28 सितंबर को एफिल टॉवर के सामने 'प्लेस जोफ्रे' में आयोजित पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया।



इस शो में केंडल जेनर, इवा लोंगोरिया, सेलीन डियोन, सिमोन एशले, वियोला डेविस, जेन फोंडा, कारा डेलेविंगने और एंडी मैकडॉवेल जैसी ग्लोबल हस्तियां और एंबेसडर शामिल हुए। स्टेज पर ऐश्वर्या और अन्य ग्लोबल हस्तियां काफी मस्ती करती दिखीं और रैंप वॉक करते समय ऐश्वर्या ने क्राउन भी पहना था। ऐश्वर्या राय गहरे रंग की मखमली (वेलवेट) पोशाक में नजर आईं, जिस पर बारीक नक्काशी और क्रिस्टलों से जड़ा हुआ केप बेहद खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ ही, उनके नए बरगंडी-लाल बालों ने उनके इस अंदाज को एक आधुनिक और शानदार लुक दिया। ऑनलाइन कई लोगों ने ऐश्वर्या को 'रॉयल्टी' कहा और पेरिस इवेंट में उनके लुक की तारीफ भी की। एक और वीडियो में ईवा लोंगोरिया और ऐश्वर्या को बैकस्टेज एक-दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए देखा गया। हाल ही में ऐश्वर्या को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था, जब वह इस इवेंट के लिए पेरिस जा रही थीं। ग्लोबल फैशन और सिनेमा इवेंट्स से ऐश्वर्या का जुड़ाव 2002 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनकी पहली मौजूदगी से शुरू हुआ था। समय, वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए फेस्टिवल में पहुंची थीं, जिसे इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में दिखाया गया था। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और को-स्टार शाहरुख खान के साथ, ऐश्वर्या ने पारंपरिक पीली साड़ी में यादगार एंट्री की थी। तीनों एक घोड़ा-गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे थे। अगले साल, वह फीचर-फिल्म जूरी की सदस्य के तौर पर फेस्टिवल में लौटीं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनीं।

जब टॉम ऑल्टर ने पहली बार लिया सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू, मास्टर ब्लास्टर के जवाब ने खींचा था ध्यान

अभिनेता टॉम ऑल्टर ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका चेहरा बेशक विदेशी था, लेकिन उनकी भाषा, थिएटर से जुड़ाव और भारतीय संस्कृति की समझ ने दर्शकों के दिल में जगह बना ली।

उन्होंने फिल्मों के साथ टीवी और थिएटर में भी लंबे समय तक काम किया। टॉम ऑल्टर की जिंदगी का एक किस्सा ऐसा भी है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास से जोड़ता है। जनवरी 1989 में उन्होंने सिर्फ 15 साल के एक युवा क्रिकेटर का पहला टीवी इंटरव्यू लिया था। वह युवा सचिन तेंदुलकर थे। कैमरे के सामने सचिन ने बेहद कम शब्दों में जवाब दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था, ' 'मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है।'' टॉम ऑल्टर का जन्म 22 जून 1950 को मसूरी में हुआ था। उनके परिवार की जड़ें अमेरिका से जुड़ी थीं, लेकिन टॉम का जन्म और परवरिश भारत में ही हुई। उन्होंने मसूरी में स्कूली पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने कुछ समय टीचर के तौर पर भी काम किया। 1970 के दौर में एक फिल्म ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की 'आराधना' देखी और फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि उसी हफ्ते वह साइकिल से 10 किलोमीटर दूर जाकर उसे कई बार देखने पहुंचे। इस फिल्म के बाद उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें एक्टर बनना है।



इसके बाद टॉम ऑल्टर ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में दाखिला लिया और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। फिल्मों में उनकी पहचान ऐसे कलाकार की बनी, जो हिंदी के साथ उर्दू पर भी अच्छी पकड़ रखता था। उनकी आवाज और बोलने का अंदाज दूसरे कलाकारों से अलग थे। 'शतरंज के खिलाड़ी', 'गांधी', 'क्रांति', 'आशिकी', 'परिंदा' और 'जुनून' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

टॉम ऑल्टर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। थिएटर उनके करियर का अहम हिस्सा था। उन्होंने कई नाटकों में काम किया और मंच पर अलग-अलग ऐतिहासिक और साहित्यिक किरदार निभाए। टीवी पर भी उनकी मजबूत पहचान बनी। 'भारत एक खोज', 'जुनून', 'जुबान संभालके' और 'बेताल पच्चीसी' जैसे शोज ने उन्हें घर-घर पहुंचाया। उन्होंने लेखन में भी हाथ आजमाया और क्रिकेट को लेकर उनकी दिलचस्पी इतनी गहरी थी कि वह खेल पर लिखते भी थे।

पति के साथ कॉमेडी शो देखने पहुंचीं प्रीति जिंटा, मैक्स अमिनी के शो की शेयर की झलकियां

अभिनेत्री प्रीति जिंटा हाल ही में अपने पति के साथ कॉमेडी शो में पहुंचीं।



वे मशहूर ईरानी-अमेरिकी स्टैंड-अप कॉमेडियन मैक्स अमिनी का शो देखने गई थीं। इस शो की कुछ मजेदार झलकियां अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर शो की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे पति जीन गुडइनफ और स्टैंड-अप कॉमेडियन मैक्स अमिनी के साथ नजर आ रही हैं। अभिनेत्री मैक्स अमिनी के परफॉर्मेंस की भी वीडियो पोस्ट की। प्रीति जिंटा ने लिखा, 'सोमवार रात बहुत मजा आया। मैक्स अमिनी का मेरा पहला लाइव कॉमेडी शो था और उन्होंने बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस दी। आप बहुत टैलेंटेड हैं मेरे दोस्त और मैं आपके लिए हमेशा और ज्यादा प्यार और तरक्की की दुआ करती हूं। ' अभिनेत्री ने मैक्स अमिनी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'शो में मुझे बुलाने और मेरा नाम लेना और सबसे ज्यादा पूरी रात हमें हंसाने के लिए और इतनी बड़ी मुस्कान के साथ घर भेजने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ढेर सारा प्यार। ' अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हाल ही में आठ साल के गैप के बाद पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' से बड़े पर्दे पर वापसी की। सनी देओल स्टारर यह एक्शन ड्रामा 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। सनी देओल की भारी आवाज, उनके दमदार डायलॉग्स और शबाना आजमी के अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा तो कुछ दर्शकों का मानना था कि फिल्म की कहानी में कमी है। इसके बाद अभिनेत्री फिल्म 'वाइब' में नजर आई, जिसमें उनके साथ कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और डेब्यूटेंट वंशिका धीर लीड रोल में हैं। कुणाल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म दो जिगरी दोस्तों- हार्दिक (कुणाल खेमू) और बग्स (स्पर्श श्रीवास्तव) के इर्द-गिर्द घूमती है। हार्दिक हाल ही में रिहैब सेंटर से बाहर आया है और ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त बग्स एक बड़ी कंपनी में काम करता है और उसकी मदद करता है।

'मिस प्रिटी इंडिया' रह चुकी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत, पुलिस जांच में जुटी

30 साल की निधि का शव शनिवार को भूसा मोड़ स्थित उनके घर में मिला। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनकी मौत से पहले की परिस्थितियों को समझने के लिए परिवार से मिली जानकारी और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।



मुंबई । मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर निधि तिवारी की घर में मौत हो गई। निधि की मौत की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। परिवार की ओर से पुलिस को बताया गया है कि शनिवार शाम निधि फोन पर किसी से बातचीत कर रही थीं। परिवार का दावा है कि बातचीत के बाद उसने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया था। पोस्ट में लिखा था, 'इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया। इसलिए कहा जाता है खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं। खुद में खुद को तलाश करो, किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे खुद को। ' बताया जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट के बाद निधि अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब परिवार के लोग उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया और खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अगले दिन काफी देर तक जब निधि ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस फिलहाल परिवार की ओर से सामने रखी गई फोन बातचीत से जुड़ी जानकारी के साथ-साथ निधि की मौत से पहले की घटनाओं और परिस्थितियों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, निधि एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थीं। इस सपने को पूरा करने के लिए वह मॉडलिंग करती थीं और लगातार डिजिटल कंटेंट भी बनाती थीं। सोशल मीडिया के जरिए वह अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं और उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग भी थी। निधि ने साल 2024 में 'मिस प्रिटी इंडिया' का खिताब भी जीता था। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक पर उनके करीब 9 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 7 लाख फॉलोअर्स थे।

2028 तक मंगल का नया भूगर्भीय नक्शा बनाएगा चीन



एजेंसी

चीन 2028 के अंत तक मंगल का नई पीढ़ी का भूगर्भीय नक्शा तैयार करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य लाल ग्रह के अरबों साल पुराने जल और जलवायु इतिहास को समझना है। इसके साथ ही चीन मंगल के भूगर्भीय इतिहास को अलग-अलग कालखंडों में बांटने के लिए अपनी वैज्ञानिक प्रणाली भी विकसित करेगा। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीनी विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद और तियानवेन-3 मंगल नमूना वापसी मिशन के मुख्य वैज्ञानिक हौ जेंगछ्येन ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने यह बात चीनी भूवैज्ञानिक विज्ञान अकादमी के भूविज्ञान संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी में कही। अमेरिका और यूरोप के आंकड़े भी होंगे शामिल नए नक्शे के निर्माण में मुख्य रूप से चीन के तियानवेन-1 मिशन से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल अभियानों से मिले आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक मंगल की तस्वीरों के अलावा उसकी सतह से जुड़े स्पेक्ट्रम, रडार, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे। इससे मंगल की सतह और उसके नीचे मौजूद भूगर्भीय संरचनाओं की अधिक व्यापक तस्वीर तैयार करने की कोशिश होगी। बनेगा मंगल का विस्तृत वैश्विक नक्शा परियोजना के तहत 2028 के अंत तक 1:50 लाख पैमाने का मंगल का भूगर्भीय नक्शा तैयार करने का लक्ष्य है। इसके अलावा लैंडिंग क्षेत्र का 1:50,000 पैमाने का अधिक विस्तृत नक्शा और अलग- अलग विषयों पर आधारित कई एटलस तैयार किए जाएंगे। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के तहत मंगल का दुनिया का पहला इंटेलिजेंट जियोलॉजिकल मैप भी जारी किया जाएगा। चीन का कहना है कि भविष्य में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल चंद्रमा, शुक्र और क्षुद्रग्रहों के भूगर्भीय नक्शे तैयार करने में किया जा सकता है।

एआई करेगा अरबों आंकड़ों का विश्लेषण

इस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वैज्ञानिकों के भूगर्भीय अनुभव और नियमों को एआई आधारित बड़े मॉडलों में शामिल किया जाएगा, ताकि मशीन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को समझना और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना संभव हो। तकनीक का इस्तेमाल छोटे स्तर पर मौजूद खनिजों की पहचान से लेकर बड़े स्तर पर मंगल की भूगर्भीय और टेक्टोनिक संरचनाओं को समझने तक किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एआई केवल मंगल की तस्वीरों को पहचानने का काम नहीं करेगा, बल्कि अलग-अलग प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़ों को जोड़कर यह समझने में भी मदद करेगा कि मंगल की सतह समय के साथ कैसे बदली।

क्यों महत्वपूर्ण है मंगल का भूगर्भीय नक्शा?

मंगल का भूगर्भीय नक्शा सिर्फ उसकी सतह का नक्शा नहीं होगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि मंगल पर पानी कहां मौजूद था, उसकी सतह पर किस तरह के भूगर्भीय बदलाव हुए और ग्रह की जलवायु अरबों वर्षों में कैसे बदली। चीन के भूवैज्ञानिक विज्ञान अकादमी के निदेशक यांग झिमिंग के अनुसार, संस्थान पिछले 70 वर्षों से भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने का काम कर रहा है। यह काम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नक्शों से आगे बढ़कर चंद्रमा और अब मंगल तक पहुंच चुका है। उनके मुताबिक ऐसे नक्शे ग्रहों पर भविष्य में कहां जाना है, क्या तलाशना है और किन वैज्ञानिक सवालों के जवाब खोजने हैं, यह तय करने में आधार प्रदान करते हैं।

झुरोंग रोवर ने दिए मंगल के पानी के संकेत

चीन का झुरोंग रोवर 2021 में तियानवेन-1 मिशन के तहत मंगल की सतह पर उतरा था। इससे मिले आंकड़ों ने मंगल के प्राचीन जल इतिहास को समझने में नई जानकारी दी है। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले तक एक विशाल प्राचीन महासागर मौजूद रहा हो सकता है। इसके अलावा करीब 1.6 अरब साल पहले अल्प अवधि की बाढ़ आने के संकेत भी मिले हैं। इन संकेतों को मंगल की जलवायु के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए भूगर्भीय नक्शे में इन निष्कर्षों को भी शामिल किया जाएगा।

मंगल के इतिहास को नए तरीके से बांटेगा चीन

फिलहाल मंगल के भूगर्भीय इतिहास को मुख्य रूप से तीन बड़े कालखंडों में बांटा जाता है नोआकियन, हेस्पेरियन और अमेजोनियन। इन कालखंडों की पहचान मुख्य रूप से मंगल की सतह पर दिखाई देने वाले उल्कापिंडों के गड्ढों की संख्या और उनकी घनत्व के आधार पर की गई है। इनकी सटीक अवधि को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अध्ययन जारी है। चीन अब मंगल के भूगर्भीय समय को विभाजित करने के लिए अपनी नई प्रणाली विकसित करना चाहता है। चीनी वैज्ञानिकों का लक्ष्य इस प्रणाली को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानक बनाने का है।

पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाईवे पर कराची फुटबॉल टीम को लूटा



एजेंसी

पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। कराची की 'डिस्ट्रिक्ट वेस्ट' की एक स्थानीय फुटबॉल टीम, जो 'चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप' टूर्नामेंट में हिस्सा लेने कराची से क्वेटा जा रही थी, उसे रास्ते में एक सशस्त्र उग्रवादी गिरोह ने रोककर गनपॉइंट पर लूट लिया। सोमवार शाम मस्तंग और सरियाब के बीच नेशनल हाईवे पर लगभग 12 हथियारबंद बदमाशों ने टीम की बस को जबरन रुकवाया। इसके बाद पूरी टीम और अधिकारियों को गनपॉइंट पर बस से नीचे उतारकर उनके मोबाइल फोन, नकदी और सारा कीमती सामान लूट लिया गया।

बंदूक की बट से मारा से मारा: टीम मैनेजर ने सुनाई आपबीती

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टीम मैनेजर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस भयावह आपबीती के बारे में बताते हुए कहा कि नकाबपोश बंदूकधारियों ने अचानक बस को घेर लिया और सभी खिलाड़ियों को तुरंत नीचे उतरने का हुक्म दिया। मैनेजर ने खुलासा किया कि डकैती के दौरान विरोध करने या देरी करने पर बदमाशों ने कुछ खिलाड़ियों और अधिकारियों पर राइफल और बंदूक के कुंदों से हमला भी किया और उन्हें पीटा।

लूटपाट के बाद किसी तरह क्वेटा पहुंची पूरी टीम के पास खाने-पीने और रहने तक के पैसे नहीं बचे थे। घटना की जानकारी मिलने पर बलूचिस्तान के खेल मंत्री ने हस्तक्षेप किया और बेबस खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन दैनिक भत्ते और रहने का इंतजाम करवाया।

हमने बस से जाने से मना किया था: सिंध फुटबॉल एसोसिएशन

इस दर्दनाक वारदात के बाद टीम के सड़क मार्ग से यात्रा करने के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद आजम ने बताया कि बलूचिस्तान के बिगड़े सुरक्षा हालात को देखते हुए एसोसिएशन ने अपनी आधिकारिक राज्य टीम को टूर्नामेंट में न भेजने का फैसला किया था।

मोहम्मद आजम ने कहा, ₹हमने अपनी सिंध टीम को वहां नहीं भेजा और कराची के सभी लोकल क्लबों को भी सख्त हिदायत दी थी कि सुरक्षा कारणों से कोई भी बस या ट्रेन से क्वेटा न जाए। लेकिन कराची वेस्ट की टीम फिर भी बस से चली गई, और जिस बात का हमें डर था, आखिरकार वही हुआ।

उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फुटबॉल संघों ने भी इस टूर्नामेंट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अपनी टीमें भेजने से साफ इनकार कर दिया था।

बलूचिस्तान के हाईवे बने 'डेंजर जोन'

यह घटना बलूचिस्तान में गहराते सुरक्षा संकट की एक बानगी भर है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फुटबॉल टीम के साथ हुई इस वारदात से ठीक कुछ दिन पहले डेरा बुगटी इलाके से दो स्थानीय क्रिकेटरों का भी अपहरण कर लिया गया था।

खासतौर से मस्तंग को क्वेटा से जोड़ने वाला हाईवे यात्रियों के लिए एक बड़ा 'हॉटस्पॉट' और 'डेंजर जोन' बन चुका है, जहां आए दिन हथियारबंद गिरोह और अलगाववादी उग्रवादी यात्रियों को निशाना बनाते हैं। इसके बावजूद खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होना प्रशासन की बड़ी नाकामी माना जा रहा है।

नेपाल में 637 पर्वतारोहियों को 18 पर्वतों पर चढ़ाई की अनुमति



एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में 2026 के शरद ऋतु के पर्वतारोहण सत्र के लिए 68 दलों के कुल 637 पर्वतारोहियों को 18 अलग-अलग पर्वतों पर चढ़ाई की अनुमति मिली है। पर्यटन विभाग के अनुसार, अनुमति पाने वाले पर्वतारोहियों में 474 पुरुष और 163 महिलाएं शामिल हैं। विभाग ने पर्वतारोहियों से 23.85 करोड़ नेपाली रुपये रॉयल्टी के रूप में एकत्र किए हैं। पर्यटन विभाग के सूचना अधिकारी सूरज घिमिरे के अनुसार, सबसे अधिक 500 पर्वतारोहियों वाले 43 दलों को माउंट मनास्लु पर चढ़ाई की अनुमति मिली है। मनास्लु के पर्वतारोहियों से विभाग ने 22.58 करोड़ नेपाली रुपये रॉयल्टी प्राप्त की है। इसी तरह 34 पर्वतारोहियों को धौलागिरी-1, 20 को पुथा हिमचुली, 16 को डांगा हिमचुली और 10 पर्वतारोहियों को बरुन्स्ते पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने मकालू, गंगापूर्णा वेस्ट, थोरोंग पीक, अन्नपूर्णा-4, पुमोरी और थापा पीक (धम्पुस) समेत अन्य पर्वतों पर भी चढ़ाई की अनुमति प्रदान की है। नेपाल में शरद ऋतु को पर्वतारोहण के प्रमुख मौसमों में से एक माना जाता है और इस दौरान विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में पर्वतारोही हिमालय की चोटियों पर अभियान के लिए पहुंचते हैं।

अमेरिका की मोस्ट वॉन्टेड टॉप 10 लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम



एजेंसी

अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने सोमवार को गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को 10 मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 10 लाख डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) के इनाम की घोषणा की गई। एफबीआई ने कहा कि सतिंदरजीत सिंह के लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कथित रूप से शामिल होने को लेकर उसकी तलाश है। एजेंसी के अनुसार यह समूह दक्षिणी कैलिफोर्निया के साथ-साथ अमेरिका और कनाडा में विभिन्न हिंसक गतिविधियों में कथित रूप से शामिल है। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ पर राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की कथित हत्याओं, गोलीबारी, अपहरण, जबरन वसूली, हमले तथा मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। वह अमेरिका में रह रहा है और उत्तरी अमेरिका में इस गिरोह का कथित प्रमुख है।

रख दिया 10 करोड़ का इनाम

निज्जर की हत्या करवाने का आरोप

आरोप है कि गोल्डी बराड़ ने ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई थी। इसके बाद भारत और कनाडा में तनाव बहुत बढ़ गया था। हालांकि कनाडा में सरकार बदलने के बाद दोनों देशों में संबंध एक बार फिर स्थिर हो गए। अमेरिका ने जुलाई में निज्जर की हत्या को लेकर पहली चार्जशीट फाइल की थी।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस रहा अमेरिका

अमेरिका पिछले कुछ दिनों से भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर शिकंजा कस रहा है। अमेरिका ऑपरेशन हाई बॉल के तहत भार से जुड़े तीन अंतरराष्ट्रीय गिरोहों पर कार्रवाई कर रहा है। इन गिरोह में शामिल 37 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अमेरिका ने भारत सरकार, रॉ. एनआईए या फिर किसी सरकारी अधिकारी पर कोई आरोप नहीं मढ़ा है। अमेरिका ने भारत से जुड़े गिरोहों का ही नाम लिया है।

फेयरफोर्ड एयरबेस पर हमले की साजिश में विदेशी देश की भूमिका की जांच कर रहा UK

एजेंसी

फेयरफोर्ड। ब्रिटिश पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या किसी विदेशी देश के लिए काम करने वाले लोग अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरबेस पर हमले की साजिश में शामिल थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच संदिग्धों को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। रविवार की सुबह लंदन के रहने वाले पांच ब्रिटिश नागरिकों (जिनकी उम्र 20-25 साल के बीच है) को हिरासत में लिया गया। एक स्थानीय किसान ने पुलिस को सूचना दी थी कि तीन सफेद वैन आरएएफ फेयरफोर्ड की ओर जा रही हैं। यह एक ब्रिटिश बेस है जहां अमेरिकी बॉम्बर विमान रखे जाते हैं और ईरान के खिलाफ मिशन पर जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि यह



संदिग्धों को किया जाएगा रिहा

ब्रिटेन की आतंकवाद-रोधी पुलिस के प्रमुख लॉरेंस टेलर ने कहा कि जिन लोगों को विस्फोटक से जुड़े अपराधों और आतंकवादी घटना की साजिश रचने के शक में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सोमवार को कड़ी जमानत शर्तों पर रिहा कर दिया जाएगा।

अभी खत्म नहीं हुई जांच

लंदन पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक बयान में टेलर ने कहा, साफ तौर पर कहूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जांच खत्म हो गई है। वे अभी भी जांच के दायरे में हैं क्योंकि हम जांच के कई पहलुओं पर काम कर रहे हैं।

घटना ईरान से जुड़ी हो सकती है और साथ ही कहा कि वह संदिग्धों को जमानत पर रिहा नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं करता। 'इसमें विदेशियों का हाथ' अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बिना कोई सबूत या जानकारी दिए कहा कि इसमें किसी विदेशी पक्ष का हाथ था। रुबियो ने सोमवार देर रात फॉक्स न्यूज नेटवर्क के हैनिटी प्रोग्राम में कहा, वीकेंड पर यूके में जो हुआ वह एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसमें साफ तौर पर किसी विदेशी पक्ष का हाथ है। मैं अभी इस बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा।

विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में सेना का हवाई हमला

एजेंसी

नई दिल्ली। बाजार के पास दो बम गिराए; 49 लोगों की मौत

म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं,58 लोग घायल हो गए। यह जानकारी विद्रोही गुट और बचाव कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने दी। सोमवार का हमला क्याउक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर (210 मील) पश्चिम में स्थित है। यह जानकारी रखाइन स्थित एक ताकतवर जातीय सशस्त्र समूह 'अराकान आर्मी' ने दी, जिसका क्याउक्ताव पर नियंत्रण है। इस हमले की जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं था। जवाबी कार्रवाई का एलान बयान में कहा गया है कि समूह 'उन लोगों और संगठनों के खिलाफ जल्द ही प्रभावी जवाबी कार्रवाई करेगा जो



जानबूझकर किए गए हवाई हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं।' बचाव कार्य के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा? रखाइन में बचाव कार्य से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी वाई हुन आंग ने घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों का हवाला देते हुए 'द एसोसिएटेड प्रेस' को हताहतों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह बाजार इलाके का मुख्य थोक केंद्र था, जहां पूरे राज्य से व्यापारी और खरीदार आते थे। उन्होंने कहा, 'यह रखाइन में हुए सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक है।' अराकान आर्मी एक ऐसे आंदोलन का अच्छी तरह से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस मिलिट्री विंग है, जो म्यांमार की केंद्रीय सरकार से रखाइन के जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहा है। इसने नवंबर 2023 में रखाइन में हमला शुरू किया और तब से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मिलिट्री हेडक्वार्टर और राज्य के 17 टाउनशिप में से 14 पर कब्जा कर लिया है। रखाइन में लड़ाई तेज होने के बाद से सेना ने व्यापार मार्गों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे भोजन की कमी और गंभीर हो गई है। दिसंबर में, रखाइन के म्राउक-यू टाउनशिप में एक अस्पताल पर सेना के हवाई हमले में कम से कम 34 लोग मारे गए और 80 अन्य घायल हो गए।

म्यांमार में क्या हो रहा है?

यह हमला पश्चिमी रखाइन राज्य में हुआ। देश भर में लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुटों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ किए जा रहे घातक हवाई हमलों की कड़ी में सबसे ताजा घटना है। 1 फरवरी, 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीनने के बाद से ही म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को घातक बल प्रयोग से दबाए जाने के बाद, सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए, जिससे देश के बड़े हिस्से संघर्ष की चपेट में आ गए।

क्या इस हमले को लेकर सेना ने जवाब दिया है?

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में इमारतों में आग लगी हुई, क्षतिग्रस्त वाहन और पास के एक पुल का कुछ हिस्सा नष्ट हुआ दिखाई दिया। सेना ने इस हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। सेना ने पहले कहा है कि वह केवल वैध सैन्य ठिकानों पर ही हमला करती है। उसने विद्रोही समूहों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है।

बयान में क्या बताया गया है?

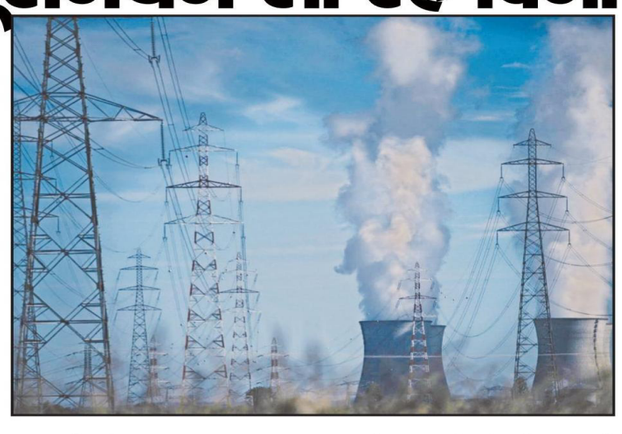
मंगलवार तड़के जारी एक बयान में अराकान आर्मी ने कहा कि दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास दो बम गिराए, जिसमें सामान बेचने वाले, खरीदार और पैदल चलने वाले लोग मारे गए। समूह ने बताया कि 58 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से 22 की हालत गंभीर है।

रूस से यूरेनियम ला रहे विमान को नहीं दी मंजूरी

एजेंसी

ढाका। जिस पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठे बांग्लादेश को उसी ने धोखा दे दिया है। बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो गई है। इसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण यूनिट-2 के लिए यूरेनियम लेकर आने वाला कार्गो विमान बांग्लादेश नहीं पहुंच सका।

बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फकीर महबूब अनाम ने ANI को फोन पर बताया कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम लेकर आने वाले कार्गो विमान के 24 सितंबर को पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि, विमान को पाकिस्तानी एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली और इसी



वजह से यूरेनियम तय समय पर बांग्लादेश नहीं पहुंच सका।

पाकिस्तान ने एयरस्पेस क्लियरेंस क्यों नहीं दी?

मंत्री ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियरेंस नहीं दिए जाने की सही वजह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि यूरेनियम की बांग्लादेश पहुंचने की नई तारीख प्रस्तावित की गई है। रूस की ओर से इसके अक्टूबर के पहले सप्ताह में बांग्लादेश पहुंचने की बात कही गई है।

एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी थी

बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव शेख मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने भी इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और अधिकारी विमान का इंतजार कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि रोसाटॉम के संपर्क अधिकारी ने उन्हें बताया कि एयरस्पेस क्लियर नहीं है। इस वजह से यूरेनियम को भेजना संभव नहीं हो सका और अब इसे दोबारा शेड्यूल करना पड़ सकता है। अधिकारी यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि किस देश ने एयरस्पेस को ब्लॉक किया था।

रूस की रोसाटॉम की मदद से बन रहा है प्लांट

रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण रूस की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम की तकनीकी मदद से किया जा रहा है और इसकी निगरानी बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन कर रहा है।

यह प्लांट बांग्लादेश के पाबना जिले के ईश्वरडी उपजिला के पाकशी यूनियन में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर गांव में बनाया जा रहा है। परियोजना में तीसरी पीढ़ी के दो VVER-1200 रिएक्टर यूनिट बनाए जा रहे हैं। दोनों यूनिट की कुल क्षमता 2,400 मेगावाट बेसलोड बिजली उत्पादन की होगी।

यूनिट-1 के लिए पहले पहुंच चुका है यूरेनियम

रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट-1 के लिए लो-एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल की पहली खेप रूस से बांग्लादेश पहुंच चुकी है। रोसाटॉम के नोवोसिबिर्स्क केमिकल कंसंट्रेट्स प्लांट में तैयार किए गए 164 नए फ्यूल असेंबली को रूस से एक भारी क्षमता वाले रूसी कार्गो विमान के जरिए ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया था।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक में साल 2015 से अबतक 15 से अधिक नए द्वीपों की खोज

एजेंसी



मॉस्को। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रूसी शोधकर्ताओं ने वर्ष 2015 से आर्कटिक क्षेत्र में अलग-अलग आकार के 15 से अधिक नए द्वीपों की खोज की है। एडमिरल मकारोव स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीटाइम एंड इनलैंड शिपिंग की मैरीटाइम एकेडमी इंस्टीट्यूट के सी हाइड्रोग्राफी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर आंद्रे लियोनोव ने रिया नोवोस्ती को यह जानकारी दी। लियोनोव ने कहा कि वह नए खोजे गए द्वीपों की सटीक संख्या नहीं बता सकते, लेकिन 2015 से अब तक आर्कटिक में 15 से अधिक द्वीपों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि शोधकर्ता नई भू-आकृतियों के बनने की प्रक्रिया पर कई वर्षों तक नजर रखते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए इस प्रक्रिया को लगातार ट्रैक किया जाता है और कई बार यह सुनिश्चित करने में एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है कि सामने आई नई भू-आकृति वास्तव में एक द्वीप है। नए द्वीपों के बनने के कारणों का उल्लेख करते हुए हाइड्रोग्राफर ने जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आउटलेट ग्लेशियरों के किनारे पीछे हट रहे हैं। ग्लेशियरों के पीछे हटने से पहले बर्फ से ढके रहने वाले कुछ क्षेत्र धीरे-धीरे सामने आने लगते हैं और नई भू-आकृतियों की पहचान संभव होती है। लियोनोव ने कहा कि रिमोट सेंसिंग तकनीक में हुई प्रगति ने समुद्र तटों में होने वाले बदलावों का पता लगाना आसान बना दिया है। पहले शोधकर्ताओं को नई भू-आकृतियों की पहचान के लिए इन दुर्गम इलाकों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना पड़ता था।

स्वत्वाधिकारी एक्सपर्ट टाइम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, सम्पादक जितेन्द्र कुमार द्वारा शॉप नम्बर-2 प्लॉट नम्बर-17, ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक एल-3, नियर भोला चौक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं मुद्रक दिनेश शर्मा द्वारा स्वास्तिका क्रीएशन 19 डीएसआईडीसी शेड्स, स्कीम 3, ओखला फेज-2 नईदिल्ली-110020 से मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं0- DLBIL/26/A3806 मो0 नं0- 9266066092

❖पीआरबी एक्ट के अंतर्गत सभी विवादों का न्याय क्षेत्र द्वारका कोर्ट दिल्ली होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित लेख अथवा समाचार से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।